

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942-सितम्बर 14, 2020 <i>Bhadra 23, Monday, Saka 1942-September 14, 2020</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**खान (गुप-2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, दिसम्बर 24, 2019**

**संख्या प.14(9)खान/गुप-2/2015 पार्ट II :-** राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/गुप-2/2015 पार्ट II दिनांक 30.08.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,  
शुभम चौधरी,  
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 30 अगस्त, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(i) नियम 5 के पार्श्व शीर्ष में, विद्यमान अभिव्यक्ति “खनन पट्टा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति” प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “नियम 16 के उप-नियम (2), (3), और (4)” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ नियम 16 या, यथास्थिति, नियम 17” प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (iii) उप-नियम (2) के विद्यमान परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “पट्टा विलेख के निष्पादन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ पट्टा विलेख के निष्पादन या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iv) उप-नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “खनन पट्टे का निष्पादन और पंजीयन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “खनन पट्टे का निष्पादन और पंजीयन या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना” प्रतिस्थापित की जायेगी।
3. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 में,-
- (i) उप-नियम (2) के खण्ड (iii) के तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “स्थिर भाटक” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुज्ञप्ति शुल्क” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता” के स्थान पर अभिव्यक्ति “खदान अनुज्ञप्ति संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा स्वीकृत की जायेगी और आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता” प्रतिस्थापित की जायेगी।
4. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति “पंजीयन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “निष्पादन” प्रतिस्थापित की जायेगी।
5. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 में,-
- (i) उप-नियम (1) के खण्ड (xv) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क” के स्थान पर अभिव्यक्ति “विद्यमान स्थिर भाटक या सम्मिलित किये जाने वाले खनिज के स्थिर भाटक, जो भी उच्चतर हो, या, यथास्थिति, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-नियम (2) के खण्ड (iv) के उप-खण्ड (ख) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “और प्रेषण” हटायी जायेगी।
6. नियम 37 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 37 के उप-नियम (7) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) की विद्यमान मद संख्यांक (VI) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
- “(vi) विभाग में ठेकेदार के पंजीयन की स्कैन प्रति;”
7. नियम 44 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 44 के उप-नियम (10) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “संकर्म ठेकेदार को पृथक अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “संकर्म ठेकेदार को पृथक अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा और यदि खनिज विद्यमान पट्टों से अभिप्राप्त किया गया है तो पट्टेदार को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पृथक संदत्त रवन्ना जारी किया जायेगा। ऐसे संकर्म ठेकेदार से प्राप्त अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र शुल्क ठेका राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।” प्रतिस्थापित की जायेगी।
8. नियम 51 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 51 के उप-नियम (7) में विद्यमान अभिव्यक्ति “अल्पावधि अनुज्ञापत्र की कालावधि” के स्थान पर अभिव्यक्ति “क्षेत्र जिसके लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जा सकेगा एक हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा और ऐसे अनुज्ञापत्र की कालावधि” प्रतिस्थापित की जायेगी।
9. नियम 54 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 54 के उप-नियम (3) के प्रथम परन्तुक के नीचे आयी सारणी में,-

- (i) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “हाफ बाडी ट्रक” के स्थान पर अभिव्यक्ति सोलह टन तक सकल वाहन भार वाले ट्रक/डंपर/कोई अन्य वाहन (वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र के अनुसार)” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति “फुल बाडी ट्रक, डंपर, ट्रैला” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ सोलह टन से अधिक सकल वाहन भार वाले ट्रक/डंपर/कोई अन्य वाहन (वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र के अनुसार) और” प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 60 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 60 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “अधीक्षण खनि अभियंता,” के पश्चात और विद्यमान अभिव्यक्ति “खनि अभियंता” के पूर्व अभिव्यक्ति “अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता),” अन्तःस्थापित की जायेगी।

11. अनुसूची 6 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 6 में,-

- (i) मद संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “कैलकेरियस सैण्ड” हटायी जायेगी; और
- (ii) विद्यमान मद संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात और विद्यमान मद संख्यांक 12 और उसकी प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित नयी मद संख्यांक 11क और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात:-

“

11क	ख.अ./स.ख.अ.	27	खदान अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए आवेदन का निपटारा करना	उनकी अधिकारिता के भीतर-भीतर पूर्ण शक्तियां
-----	-------------	----	---	--

”

12. प्रारूप-22 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-22 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (x) में विद्यमान अभिव्यक्ति “अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा और यदि खनिज विद्यमान पट्टों से अभिप्राप्त किया गया है तो पट्टेदार को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पृथक संदत्त रवन्ना जारी किया जायेगा। ऐसे संकर्म ठेकेदार से प्राप्त अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र शुल्क ठेका राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।” जोड़ी जायेगी।

[सं. एफ.14(9)खान/गुप-2/2015-पार्ट-II,  
राज्यपाल के आदेश से,  
इकबाल,  
संयुक्त शासन सचिव